137

संख्या/1884/XVIII(II)/2012-18(39)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक: 17 दिसम्बर, 2012

**विषयः-सशस्त्र सीमा बल के सीमा चौकी क्वीतड़ की स्थापना हेतु ग्राम सकुन, पटवारी क्षेत्र क्वीतड़, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ में 0.501 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-558/सात-31/2011-12 दिनांक-21.04.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, सशस्त्र सीमा बल के सीमा चौकी क्वीतड़ की स्थापना हेतु ग्राम सकुन, पटवारी क्षेत्र क्वीतड, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ में 0.501 है0 भूमि सशस्त्र सीमा बल को गृह विभाग की सहमति/अनापत्ति के कम में शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान प्रचलित बाजार दर से भूमि की कीमत के अतिरिक्त माल गुजारी के 100 गुना के बराबर धनराशि पूंजीकृत मूल्य के रूप में एक मुश्त जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3 प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।

4- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

5 यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

.........2

6– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7– प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

8– इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी)संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

9– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 8 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0– /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2–अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड देहरादून।
3–आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4–सेनानायक, पांचवी वाहनी सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ।
5–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6–प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।